



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 2003/चैत्र 20, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 2003/CHAITRA 20, 1925

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 329(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2003 है
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (5) में -
(क) खंड (v) में, अंत में आने वाले 'और' शब्द का लोप किया जाएगा।
(ख) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
' (v क) खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 3 के खंड ए में यथा परिभाषित उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना ; और'।
3. उक्त नियमों के नियम 22 ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा ;
अर्थात् :-

'22 ग खनन पट्टे का न्यूनतम आकार-खनन पट्टे की मंजूरी के लिए न्यूनतम क्षेत्र,

निम्नलिखित से कम नहीं होगा -

(क) उथली प्रकृति के, एकाकी और अनुदैर्घ्य लम्बाई में 200 मी० से अनधिक लघु निष्केपों (जो किसी बड़े निष्केप का विखंडित भाग नहीं है) की बाबत, एक हेक्टेयर। ये निष्केप या तो मूल रूप या भौगोलिक विक्षोभों के कारण अभिस्थापन या विस्थापन के परिणामस्वरूप लघु निष्केप हैं। लघु निष्केपों के अंतर्गत यांत्रिक अपक्षयन और निष्केपण के कारण विरचित (परिवहनित) प्लवित निष्केप, जलौढ़ या अपोढ़ स्थानक (दबे हुए या अन्यथा) भी हैं; जिनकी सामान्यतः समुद्रतट या स्थानक के सिवाय विशिष्ट सपाकृति हैं।

(ख) समुद्र तट या स्थानक की बाबत दो हेक्टेयर।

समुद्र तट या स्थानक एक या बहु खनिज संकेन्द्रण है जिनके अंतर्गत तटीय समुद्री रेखा पर या उससे परे आने वाले बालू के टीले भी हैं। ये निष्केप ज्वार भाटा, लहरों और अभितट धाराओं के उतार-चढ़ाव के उत्पाद हैं और कुछ स्थानों पर अर्द्ध-समेकित से समेकित तक की प्रकृति के हैं।

(ग) ऊपर खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न सभी खनिज निष्केपों की बाबत चार हेक्टेयर।¹

4. उक्त नियमों के नियम 29 में -

(क) उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, शर्त (ख) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(ग) पट्टेदार के नियम 29 क के अधीन प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है।"

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) बीमाकृत राशि को समपहृत करने के लिए या खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 23 च के उपनियम (6) के अधीन, पट्टेदार द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 23 क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुमोदित खान बंद करने की योजना में अंतर्विष्ट उपायों के अनुपालन पर, यथास्थिति, प्रादेशिक खान नियंत्रण या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने पर यह राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह अनुमोदित खान बंद करने की योजना में यथा अंतर्विष्ट संरक्षा, पुनरोद्धार एवं पुनर्स्थापन उपायों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए वित्तीय आश्वासन के रूप में दिए गए या अभिप्राप्त किसी प्रत्यय पत्र या बंध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति, प्रत्याभूति को वसूल करे और ऐसे उपाय या तो स्वयं करे या ऐसा करने के लिए किसी अभिकर्ता को नियुक्त करे।"

5. उक्त नियमों के नियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"29 क. बंद करने के लिए उपबंध (1) पट्टेदार किसी पट्टे या उसके किसी भाग को तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक कि यथास्थिति, प्रादेशिक नियंत्रक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा

प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना, अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वित नहीं कर दी जाती है। (2) उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, पट्टेदार से, यथास्थिति प्रादेशिक खान नियंत्रक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी कि पट्टेदार द्वारा अनुमोदित खान बंद करने की योजना या ऐसे उपांतरणों सहित जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हों, के अनुसार संरक्षा, पुनरोद्धार एवं पुनर्स्थापन कार्य पूरा कर दिया गया है।"

6. उक्त नियमों के नियम 64 घ में, मार्गदर्शक सिद्धांत शीर्षक के अधीन :

88(क) मामला 1 : खान स्वामियों द्वारा घरेलू बाजार में विक्रीत खनिजों के लिए, और मामला 2 : ऐसे खनिजों के लिए, जो निर्यात किए जाते हैं और उससे संबंधित वर्णन के स्थान पर निम्नलिखित मामले और वर्णन रखे जाएंगे, अर्थात् :-

'मामला 1 : सभी गैर-परमाणु और गैर ईंधन और खनिज एल्यूमिनियम, प्राथमिक स्वर्ण, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल और टिन से भिन्न खनिज, -

भारतीय खान व्यूरो 'खनिज उत्पादन के मासिक आंकड़े' प्रकाशित करता है जिसमें किसी राज्य में किसी मास के दौरान उत्पादित प्रत्येक खनिज का राज्यवार कुल मूल्य अंतर्विष्ट होता है। 'खनिज उत्पादन के मासिक आंकड़े' में भारतीय खान व्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित विभिन्न व्यष्टिक खनिजों के लिए राज्य वार औसत मूल्य, उस राज्य की किसी खान में किसी मास के दौरान किसी समय उत्पादित किसी खनिज की बाबत संबद्ध राज्य सरकार द्वारा स्वामिस्व की संगणना के लिए मुख्य आधार होगा। स्वामिस्व की संगणना के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार इस मुख्य आधार मूल्य में 20% जोड़ेगी। यह मूल्य स्वामिस्व की संगणना के प्रयोजन के लिए विक्रय कीमत के रूप में गणना में लिया जाएगा। 'खनिज उत्पादन के मासिक आंकड़े' के नवीनतम प्रकाशित संस्करण में प्रकाशित खनिजों का मूल्य भी, इस बात पर विचार किए बिना कि राजस्व वस्तुतः कब उद्भूत होता है, पूर्व मास में खनन किए गए खनिज के लिए लागू समझा जाएगा। यदि किसी विशिष्ट खनिज के लिए किसी विशिष्ट संस्करण में किसी राज्य के लिए जानकारी प्रकाशित नहीं होती है तो पूर्व संस्करण में राज्य में उस खनिज के लिए उपलब्ध अंतिम जानकारी निर्दिष्ट की जाएगी, जिसके न हो सकने पर संपूर्ण भारत के लिए खनिज के लिए नवीनतम प्रकाशित जानकारी निर्दिष्ट की जाएगी।

मामला 2 : परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन विहित सभी परमाणु खनिजों के लिए :

इस प्रवर्ग के अधीन खनिजों में तटीय राज्यों में मुख्यतः समुद्रतट बालू निक्षेपों से अभिप्राप्त इल्मेनाइट, ल्यूकोक्सीन, रुटाइल और जरकन सम्मिलित है। राजस्व के संग्रहण का आधार खनन की गई समुद्रतट बालू में वास्तविक खनिज अन्तर्वस्तु होगा।

(क) घरेलू बाजार में विक्रय की दशा में, मूल्यानुसार राजस्व की संगणना के लिए खनन स्वामियों द्वारा

उनके विक्रय वाउचर या बिल या बीजक में यथा दर्शित पट्टा की सीमा से विक्रय के बिन्दु तक परिवहन की लागत घटा कर वस्तुतः प्राप्त पृथक किए गए खनिज की प्रतिटन विक्रय कीमत पर विचार किया जाएगा । स्वामिस्व पर करों के संदाय से बचने के लिए खान स्वामी, अपने हित में स्वामिस्व सहित समग्र कीमत उपदर्शित करने के बजाए विक्रय वाउचरों या बिलों या बीजकों में पृथक-पृथक कीमत और स्वामिस्व अभिलिखित कर सकते हैं । यदि कीमत स्वामिस्व और परिवहन लागत पृथक रूप से दर्शित नहीं की जाती है तो यह धारणा की जाएगी कि विक्रय वाउचरों या बिलों या बीजकों में उपदर्शित कीमत स्वामिस्व और परिवहन लागत छोड़ कर है और स्वामिस्व, तदनुसार, प्रभारित किया जाएगा,

(ख) खान स्वामियों द्वारा सीधे निर्यात की दशा में, राजस्व के प्रयोजन के लिए विक्रय मूल्य, साधारणतः पट्टे की सीमा से पत्तन तक परिवहन प्रभार, पत्तन पर लदाई और उत्तराई प्रभार पत्तन प्रभार (जिले के अंतर्गत नमूना और विश्लेषण और नुकसानी प्रभार, यदि कोई है) बीमा प्रभार, स्वामिस्व, कर और निर्यात के लिए उधार पर व्याज प्रभार घटाकर प्राप्त पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत होगी । तथापि, लागत बीमा और भाड़ा विक्रय की दशा में, समुद्री भाड़ा बीमा और गन्तव्य पत्तन पर उत्तराई की लागत भी ऐसी कीमत से घटा दी जाएगी । ऐसे प्रयोजनों के लिए खान का स्वामी, यथास्थिति, पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत या लागत बीमा भाड़ा कीमत और अन्य प्रभार पृथक रूप से उपदर्शित करते हुए बीजक या बिल तैयार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : ग्रहीत खानों (एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, निकल, स्वर्ण और चांदी से भिन्न) में उत्पादित और वास्तविक रूप से विक्रय न किए गए खनिजों के मामले में स्वामिस्व की संगणना के प्रयोजनों के लिए, मामला 1 और मामला -2 लागू होंगे ।¹ :

(ख) मामला 5 : ग्रहीत खानों में उत्पादित खनिजों के लिए (एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन निकल, स्वर्ण और चांदी से भिन्न) और जिनका वास्तविक रूप से विक्रय नहीं हुआ है और उससे संबंधित वर्णन का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 7(1)/2003-खान-6]

एस. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट :— मूल नियम दिनांक 26.11.1960 के जी एस आर सं. 1398 के द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे (दिनांक 11.11.1960 की अधिसूचना सं. एम-II-159(1)/57 और अंतिम बार दिनांक 29.10.2002 की जी एस आर सं. 733 (ई) द्वारा संशोधित (दिनांक 29.10.2002 की अधिसूचना सं. 7/5/2002-एम VI) हुए ।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2003

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 22 of the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (5),-
 - (a) in clause (v), the word “and”, occurring at the end, shall be omitted;
 - (b) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

“(va) a progressive mine closure plan as defined in clause (oo) of rule 3 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988; and”.
3. After rule 22C of the said rules, the following rule shall be inserted, namely : -

“22 D. Minimum size of the mining lease.- Minimum area for grant of mining lease shall not be less than -

- a) One hectare, in respect of small deposits (not fragmented portions of larger ones), shallow in nature, isolated and not exceeding more than 200 metres in strike length. These deposits are small by virtue of either origin or mode of emplacement or dislocation due to geological disturbances.

Small deposits shall also include float deposits (transported) formed due to mechanical weathering and deposition, alluvial or eluvial placers (buried or otherwise), which generally have peculiar configurations excepting beach sands or placers;

- (b) Two hectares, in respect of beach sands or placers.

Beach sands or placers are mono or multi mineral concentrations, including the dunes occurring on and off the coastal shore line.

These deposits are the products of ebb and flow of tides, waves and inshore currents, and at places semi-consolidated to consolidated in nature;

c) Four hectares, in respect of all mineral deposits other than those specified under clauses (a) and (b).”.

4. In rule 29 of the said rules, -

(a) in sub-rule(1), in the second proviso, after condition (b), the following condition shall be inserted; namely :-
“(c) the lessee has obtained a certificate under rule 29A.”.

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(3) Upon the issuance of the order by the Regional Controller of Mines or the officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, under sub-rule (6) of rule 23F of Mineral Conservation and Development Rules, 1988, for forfeiting the sum assured, on non-performance of the measures contained in the approved mine closure plan referred to in sub-rule (1) of rule 23A of Mineral Conservation and Development Rules, 1988 by the lessee, it shall be the responsibility of State Government to realize any letter of credit or bond or any other surety, guarantee provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective, reclamation and rehabilitation measures as contained in the approved mine closure plan and shall carry out such measures either by itself, or appoint an agent to do so.”.

5. After rule 29 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“29A. Provision for closure. - (1) The lessee shall not determine the lease or part thereof unless a final mine closure plan duly approved by the Regional Controller or the officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, is implemented as per the approval.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the lessee shall be required to obtain a certificate from the Regional Controller of Mines or officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, to the effect that protective, reclamation and rehabilitation work in accordance with the approved mine closure plan or with such modifications as approved by the competent authority have been carried out by the lessee.”.

6. In rule 64 D of the said rules, under heading Guidelines;

(a) for Case 1: For minerals sold in domestic market by the mine-owners, and Case 2: For minerals which are exported and the description relating thereto, the following Cases and descriptions shall be substituted, namely:-

“Case 1: All non atomic and non fuel minerals and minerals other than aluminium, primary gold, silver, copper, lead, zinc, nickel and tin -

The Indian Bureau of Mines publishes ‘Monthly Statistics of Mineral Production’ which contains state-wise total value of each mineral produced during a month in a State. The State-wise average value for different individual minerals as published by Indian Bureau of Mines in the ‘ Monthly

Statistics of Mineral Production' shall be the bench mark for computation of royalty by the concerned State Government in respect of any mineral produced any time during a month in any mine in that State. For the purpose of computation of royalty the State Government shall add twenty per cent to this bench mark value. This value shall be reckoned to be the sale price for the purpose of computation of royalty. Also the value of the minerals published in the latest published issue of the 'Monthly Statistics of Mineral Production' will be deemed to be applicable for the mineral mined in the previous month, irrespective of when the royalty actually accrues. If for a particular mineral, the information for a State is not published in a particular issue, the last information available for that mineral in the State in a previous issue shall be referred, failing which the latest published information for the mineral for all-India shall be referred.

Case 2 For Atomic minerals, prescribed under Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962):

The minerals under this category include ilmenite, leucoxene, rutile and zircon obtained mainly from the beach sand deposits in the coastal states. The basis of collection of royalty shall be the actual mineral content in the beach sand mined.

(a) In case of sale in the domestic market, the per tonne sale price of the separated mineral actually realized, less the cost of transportation from the lease boundary to point of sale as shown by the mine owners in their sale vouchers or bills or invoices shall be considered for computing ad valorem royalty. To avoid payment of taxes on royalty the mine owners in their own interest record the price and royalty separately in the sale vouchers or bills or invoices instead of indicating a composite price inclusive of royalty. In case the price, royalty and transportation cost are not shown separately it shall be assumed that the price indicated in the sale vouchers or bills or invoices is exclusive of royalty and transportation cost, and royalty shall be charged accordingly.

(b) In case of direct export by mine owners the sale value for the purpose of royalty shall ordinarily be the free on board (FOB) price realized less transportation charges from the lease boundary to the port, loading and unloading charges at the port, port charges (including sampling and analysis and demurrage charges, if any), insurance charges, royalty, taxes and interest charges on loan for export. However, in case of cost insurance and freight (CIF) sales, sea freight insurance and cost of unloading at the destination port shall also be deducted from such price. For such purposes the mine owner may prepare invoices or bills indicating the free on board price or cost insurance freight price as the case may be and each of the other charges separately.

Explanation – For the purposes of calculation of royalty in case of minerals produced in captive mines (other than aluminium, copper, lead zinc, tin, nickel, gold and silver) and those not actually sold, Case 1. and Case 2. shall be applicable.";

(b) Case 5: For minerals produced in captive mines (other than aluminium copper, lead, zinc, tin, nickel, gold and silver) and those not actually sold and the description relating thereto shall be omitted.

[F. No. 7(1)/2003-M.VI]

S. P. GUPTA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Official Gazette vide GSR No.1398 dated 26.11.1960 (notification no. M-II-159(1)/57 dated 11.11.1960) and lastly amended vide G.S.R. No.733(E) dated 29.10.2002 (Notification No.7/5/2002-MVI dated 29.10.2002)